AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

ग्रामीण जनसंख्या की शिक्षा समस्याएँ एवं शैक्षिक विकास योजना एक परिदृश्य

ORIGINAL ARTICLE

Author
वीणा कुमारी
शोधार्थी, भूगोल विभाग
वाईबीएन विश्वविद्यालय
रांची, झारखंड, भारत

शोध सार

किसी राष्ट्र की उन्नति वहाँ उपलब्ध समृद्ध संसाधनों पर ही निर्भर नहीं करती अपितु शिक्षित नागरिकों पर भी निर्भर करती है। मानव के सर्वांगीण विकास का मूल शिक्षा है। विकसित देशों में साक्षरता सर्वव्यापक है, परन्तु विकासशील एवं पिछड़े देशों में इसके वितरण में असमानता पाई जाती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गाँव में निवास करती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में साक्षरता दर काफी कम पाई जाती है। यहाँ शैक्षिक विकास हेतु अनेक योजनाएँ बनाई गई है फिर भी शैक्षिक पिछड़ेपर के लिए भारतीय समाज की सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियाँ मुख्य रूप से उत्तरदायी है। शिक्षा की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रभावी रणनीतियों को लागू कर सकते हैं।

मुख्य शब्द

शिक्षा, साक्षरता, विकासशील देश, जनसंख्या, ग्रामीण.

प्रस्तावना

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक मूल्यों को विकसित करने एवं सुदृढ़ बनाने के लिए यहाँ के सभी नागरिकों का शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा समाज एवं राष्ट्र के विकास का महत्वपूर्ण साधन होती है। आज के तकनीकी युग में साक्षरता का महत्व दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति राष्ट्र और समाज की वर्तमान स्थिति और अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने में सक्षम नहीं होते हैं तथा देश के विकास में उचित योगदान भी नहीं कर पाते हैं। मानव सभ्यता का विकास प्रत्यक्ष रूप से साक्षरता से संबंधित रहा है, वह राष्ट्र या समाज आर्थिक रूप से अधिक सम्पन्न है, जहाँ साक्षरता दर उच्च है और वे देश पिछड़े हुए हैं, जहाँ साक्षरता दर निम्न है। जनसंख्या संघटन या संरचना के अन्य तत्वों की तरह ही साक्षरता के क्षेत्रीय विश्लेषण को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

जनसंख्या के संघटन या संरचना का तात्पर्य उन तत्वों या पक्षों से होता है, जो मापनीय होते हैं, जैसे लिंग, आयु, व्यवसाय या आर्थिक क्रिया, ग्रामीण–नगरीय अनुपात, साक्षरता, भाषा, जाति और धर्म।

क्लार्क के अनुसार "जनसंख्या संघटन या जनसंख्या संरचना जनसंख्या के उन पक्षों को निरूपित करता है, जिसकी माप की जा सकती है।" इसका तात्पर्य है कि जनसंख्या के जिन अव्यवों के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और जनगणना से प्राप्त होते हैं, उन्हें जनसंख्या का संघटन माना जाए।

सक्षरता का अर्थ

साक्षरता का अर्थ है व्यक्ति के साक्षर होने का गुण। साक्ष्य वह व्यक्ति है जो किसी भाषा में पढ़ना और लिखना जाते हैं। साक्षरता दर किसी भी क्षेत्र की कुल जनसंख्या में पढ़े–लिखे लोगों के अनुपात को कहते हैं।

साक्षरता एक गत्यात्मक या गतिशील तथ्य है जो समय–स्थान के संदर्भ में परिवर्तनशील होती है। किसी भी राष्ट्र एवं समाज की साक्षरता स्तर का संबंध उसके आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास से प्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत की अधिकांश आबादी ग्रामीण परिवेश में जीवन निर्वाह करती है। कृषिय अर्थव्यवस्था की महत्ता के कारण गाँव में अशिक्षित परिवार शिक्षा को अधिक महत्व नहीं देते। अशिक्षा, गरीबी, रूढ़िवादी विचारधारा आदि ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता के विकास में बाधक है। नगरीय क्षेत्रों में पुरूष और महिला दोनों ही वर्गों में साक्षरता गाँव की तुलना में अधिक मिलती है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की 74.04 प्रतिशत जनसंख्या साक्षर है, जिसमें औसत ग्रामीण साक्षरता 67.8 प्रतिशत और औसत नगरीय साक्षरता 84.1 प्रतिशत है।

तालिका 1: भारत के कुछ राज्य की ग्रामीण तथा नगरीय साक्षरता दर का विवरण (2011)

राज्य	साक्षरता दर (प्रतिशत)		
	कुल	**ग्रामीण**	**नगरीय**
केरल	94.0	93.0	95.1
पश्चिम बंगाल	76.3	72.1	84.8
झारखण्ड	66.4	61.1	82.3
बिहार	61.8	59.8	76.9
महाराष्ट्र	82.3	77.0	88.7
गुजरात	78.0	71.7	86.3
मेघालय	74.4	69.9	90.8
आंध्र प्रदेश	67.0	60.4	80.1
राजस्थान	66.1	61.4	79.7

(स्रोतः Census of India, 2011, Serias 1-India Primary Census Abstract)

स्वतंत्रता के पश्चात् शिक्षा के विकास के लिए अनेक प्रयत्न किए गए हैं। सरकार द्वारा अनेक शैक्षिक विकास योजनाएँ बनाई गई है और इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ परन्तु यह भी कटु सत्य है कि शिक्षा की गुणवत्ता में कभी है और सम्पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया जा सका है। भारत में पुरूष और महिला साक्षरता तथा ग्रामीण एवं शहरी साक्षरता में अधिक भिन्नता मिलती है।

तालिका 2: भारत में साक्षरता (प्रतिशत) का विकास (1951–2011)

जनगणना वर्ष	साक्षरता जनसंख्या का प्रतिशत		
	व्यक्ति	**पुरूष**	**स्त्री**
1951	16.67	24.95	7.93
1961	24.02	34.44	12.95
1971	29.48	39.52	18.70
1981	36.23	46.89	24.82
1991	52.21	64.13	39.29
2001	64.8	75.3	53.7
2011	74.04	82.14	65.46

(स्रोतः Census of India 1991, 2001 और 2011)

साक्षरता लोकतांत्रित प्रणाली की सफलता के लिए सबसे बुनियादी मापदंडों में से एक है। किसी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। यह व्यक्ति को आत्मनिर्भर और जागरूक बनाने के लिए प्रेरणा एवं कौशल प्रदान करती है। शिक्षा वह कुंजी है, जो व्यक्ति को पूरे विश्व में आगे बढ़ने की अनुमति देती है,

बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करती है, और अपने जीवन में सफल होने में मदद करती है इसलिए शिक्षा महत्वपूर्ण है और किसी को भी इससे वंचित नहीं होना चाहिए।

सर्व शिक्षा अभियान का नारा है, "सब पढ़े सब बढ़े" इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अनेक योजनाएँ संचालित की है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा होने के बावजूद निर्धन परिवार के बच्चे विद्यालय तक नहीं जा पाते। ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा महिलाओं की शैक्षिक स्थिति अत्यंत शोचनीय है। इनके शैक्षिक पिछड़ेपन के लिए भारतीय समाज की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियाँ प्रमुख रूप से उत्तरदायी है।

ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा संबंधी समस्याएँ

- **अभिभावकों की निर्धनता**: निर्धनता के कारण माता–पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजकर किसी काम में लगाना अधिक उचित समझते हैं। गरीबी को कम करने के लिए अधिक रोजगार की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में करनी चाहिए।
- **दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली**: विद्यालय में रूचिकर वातावरण का अभाव, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, शैक्षिक सामग्री की कमी, अनुपयुक्त विद्यालय भवन, दोषपूर्ण शिक्षण विधियाँ आदि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण समस्याएँ हैं।
- **व्यवसायिक तथा तकनीकी शिक्षा की कमी**: प्रचलित पाठ्यक्रम बच्चों को समाज की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल शिक्षा प्रदान नहीं करती। व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।
- **शिक्षा की गुणवत्ता में कमी**: ग्रामीण विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में ह्रास देखने के लिए मिलता है। कक्षा छः में पढ़ने वाले छात्र कक्षा तीन की पुस्तक सरलता से पढ़ने में असमर्थ होते हैं।
- **शिक्षकों का अभाव**: ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव एक बड़ी समस्या है। कुछ विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक भी नहीं होते एक शिक्षक को दो या अधिक विषयों को भी पढ़ाना पड़ता है। एक अन्य मुख्य समस्या यह भी है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में भी संलग्न कर दिया जाता है, जिससे विद्यालयों में शिक्षा प्रभावित होती है।

विद्यालय में अपर्याप्त भौतिक एवं अन्य सुविधाएँ

ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ही विद्यालय ऐसे है जहाँ पर्याप्त भौतिक एवं बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध है। अधिकांश विद्यालय ऐसे भी है जहाँ पानी, बिजली, बेंच, भवन, शौचालय, खेल सामग्री एवं स्थान का अभाव मिलता है। विद्यालय की संख्या में कमी या घरों से अधिक दूरी पर होना बच्चों एवं अभिभावकों के लिए समस्या उत्पन्न करती है।

छात्र व्यक्तिगत भिन्नता की अवहेलना

वर्त्तमान शिक्षा पद्धति के अनुसार छात्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मुख्य पात्र होते हैं परन्तु एक समान पाठ्यक्रम होने के कारण उसकी रूचियों तथा अभिरूचियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। छात्रों की व्यक्तिगत क्षमताओं तथा सीमाओं की अवलेहना की जाती है।

प्रशासन की अनुपयुक्तता

शैक्षिक विस्तार योजना के अन्तर्गत षिक्षकों की संख्या–विद्यालय निरीक्षक, प्रशासनिक अधिकारियों की वृद्धि, स्कूलों की वृद्धि के अनुपात में नहीं की जाती जिसके परिणामस्वरूप न तो शिक्षकों के पास अपने विद्याथियो को देने के लिए पर्याप्त समय है और न ही निरीक्षकों के पास विद्यालय निरीक्षण के लिए तथा विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त समय है।

ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का अनुपात सर्वधिक है। कुछ बच्चे पारिवारिक कारण, स्कूल

संबंधित कारण तथा व्यक्तिगत कारणों से अपनी शिक्षा पूरी किए बिना बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं। ड्रॉप आउट ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी समस्या बन चुकी है। वर्ष 2016 के एएसईआर रिपोर्ट के अनुसार 6 से 14 साल के आयु वर्ग के 3.1 प्रतिशत बच्चे तथा 15 से 16 वर्ष आयु वर्ग के 13.5 प्रतिशत बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट थे।

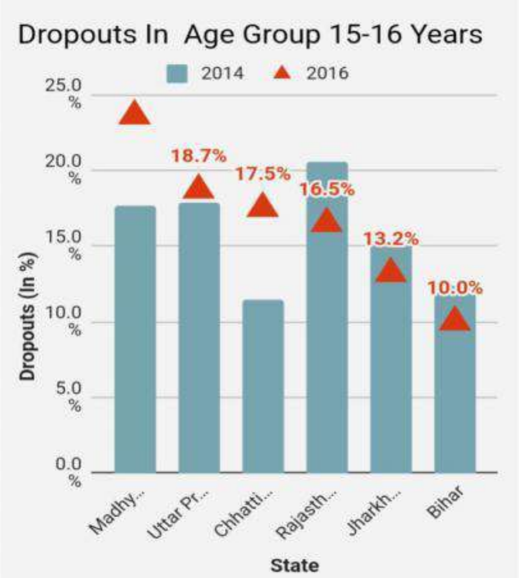

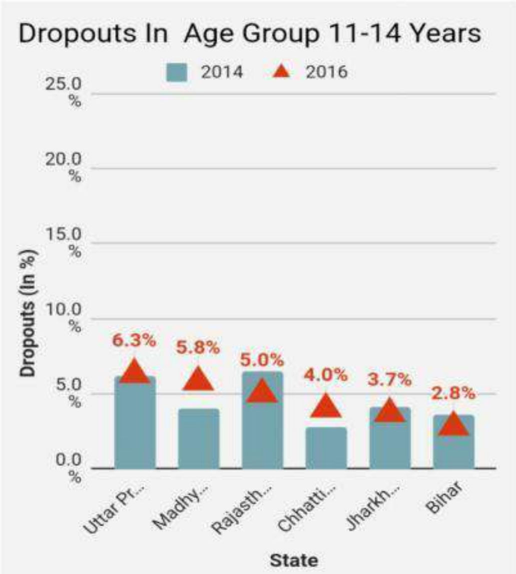

शिक्षा के विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं योग्यताएँ

- **राष्ट्रीय साक्षरता मिशन मई–1988:** विद्यालय शिक्षा के साथ प्रौढ़ शिक्षा के विकास पर बल इसका मुख्य लक्ष्य है क्योंकि साक्षरता दर मे वृद्धि तथा समाज की उन्नति के लिए प्रौढ़ का शिक्षित होना आवश्यक है।
- **महिला समाख्या योजना–1989:** महिला समाख्या योजना ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूह की महिलाओं की शिक्षा और सशक्तीकरण के लिए 1989 में प्रारंभ की गई।
- **जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम–1994:** इस कार्यक्रम का लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक करना था इसमें खर्च का उत्तरदायित्व 85 प्रतिशत केन्द्र सरकार और 15 प्रतिशत राज्य सरकार का है।
- **मध्याह भोजन योजना–1995:** यह योजना भारत तथा राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से संचालित है। इसका मुख्य लक्ष्य प्राथमिक कक्षा के नामांकन की वृद्धि, स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी करना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों में शिक्षा प्राप्त करने की क्षमता में विकास करना और छात्रों को पौष्टिक आहार प्रदान करना है।
- **सर्वशिक्षा अभियान–2001:** भारत सरकार द्वारा संचालित यह मुख्य कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना है। इसके अन्तर्गत विद्यालयी शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराना, शिक्षकों की कमी को दूर करना, शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध कराना है।
- **साक्षर भारत–2009:** इसका मुख्य उद्देश्य स्त्री एवं पुरूष के बीच साक्षरता की भिन्नता को कम करके वर्ष 2011 के 16 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक लाना। साक्षरता स्तर पर प्रतिशत शहरी ग्रामीण असमानता को दूर करना।

  इस योजना के चार महत्वपूर्ण घटक है:

  (1) कार्यात्मक साक्षरता।

  (2) बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम।

  (3) व्यवसायिक कौशल विकास कार्यक्रम।

  (4) सतत् शिक्षा कार्यक्रम।

- **शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009**: इस अधिनियम के अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को पूर्णतः मुफ्त एवं अनिवार्य कर दिया गया है। निर्धन परिवार के बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत आरक्षण प्रावधान रखा गया है।

निष्कर्ष

शैक्षिक सार्वभौमीकरण के लिए देश मे अनेक कार्यक्रम एवं योजाएँ भी संचालित की गई। जनगणना के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1951 से 2011 तक कुल साक्षरता दर में निरन्तर वृद्धि भी हुई है लेकिन स्त्री साक्षरता दर पुरूष साक्षरता दर से अभी भी कम है। इसी तरह शहरी साक्षरता दर ग्रामीण साक्षरता दर से हमेशा अधिक रही है। वर्त्तमान समय में भी ग्रामीण शैक्षिक विकास के मार्ग मे बहुत सारी समस्याएँ विद्यमान हैं जैसे अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव, शिक्षक का अभाव, शिक्षण कार्य मे परम्परागत विधियों का प्रयोग, अभिभावक की अशिक्षा के कारण शैक्षिक योजनाओं के विषय में जानकारी नहीं होना आदि। शैक्षिक विकास के लिए कई दिषाओं में कार्य किए गए परन्तु इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

अतः बच्चों का स्कूल में नामांकन होना ही काफी नहीं है विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं पर निरंतर ध्यान देना एवं उच्च कोटी की शिक्षा पर भी ध्यान देना आवष्यकता है। विद्यालय में उपस्थिति के साथ–साथ ऐसी शिक्षा मिले जिससे वे सही तरीके से पढ़ना लिखना सीख जायें।

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को सार्थक एवं सुसंगत बनाने के लिए आवश्यक है कि सभी स्तरों पर एवं पक्षों पर शिक्षा को कार्यात्मक रूप से बेहतर बनाया जाए। माता–पिता की शिक्षा के प्रति रूचि उत्पन्न करने हेतु प्रयास किए जाने चाहिए। शिक्षण अधिगम के तरीकों को आकर्षक एवं रूचिकर बनाया जाए, घर, समाज और स्कूल के वातावरण में परिवर्तन करके सकारात्मक एवं स्वस्थ बनाना आवष्यक है। शैक्षिक प्रशासकों और निरीक्षकों को शिक्षा प्रणाली से संबंधित कार्य को कड़ाई से कार्यान्वित करना चाहिए।

शिक्षा मानव एवं समाज के विकास का मूल साधन है। यह लोगों में ऐसी समझ और सामर्थ उत्पन्न करती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी प्रतिभाओं और क्षमताओं का सही तरीके से उपयोग करके स्वयं का समाज का, एवं राष्ट्र का कल्याण करने में समर्थ होता है। इस प्रकार शिक्षा विकास की अनिवार्य शर्त है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 – नई शिक्षा नीति वर्त्तमान समय की माँग और जरूरत के आधार पर देश की शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए लायी गई है। इसके अन्तर्गत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100 प्रतिशत जी ई आर के साथ प्री–स्कूल से माध्यममिक स्तर तक शिक्षा को सर्वव्यापी करना है। आशा करते हैं कि इस नई शिक्षा नीति 2020 हम सभी की आकांक्षाओं पर खरी उतरे और ग्रामीण क्षेत्र में भी साक्षरता दर उच्च हो सके।

संदर्भ सूची

1. मौर्य, एस.डी., (2020) *जनसंख्या भूगोल,* शारदा पुस्तक भवन, पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स यूनिवर्सिटी रोड, प्रयागराज–211002, पृ. 114–119।
2. अग्रवाल, जे.सी. एवं गुप्ता, एस. (2002) *शिक्षा के आधार,* शिक्षा पब्लिकेशन, दिल्ली, पृ. 87–96।
3. पाठक, पी.डी. (87–96) *भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ,* अग्रवाल पब्लिकेशन, ज्योति ब्लॉक संजय प्लेस, आगरा–2, पृ. 16–24।
4. गुप्ता, रेनू (2012) *शिक्षा के दार्शनिक, समाजशास्त्रीय और आर्थिक आधार,* टण्डन पब्लिकेशन, लुधियाना – 141008, पृ. 96–107।
5. शर्मा आर.के. एवं दुबे, एस.के. (1998) *शिक्षा के समाजशास्त्रीय परिदृश्य,* राधा प्रकाशन मंदिर प्रा.लि., नगला अजीता, आगरा, पृ. 77–83।

6. सिन्हा, सन्ध्या (2014) *भारत में शिक्षा का विकास समसामयिक मुद्दे एवं अन्य देशों से तुलनात्मक अध्ययन,* अग्रवाल पब्लिकेशन्स, संजय प्लेस आगरा– 2, पृ. 204–209।

7. भटनागर सुरेश (2011) *आधुनिक भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ,* आ. लाल बुक डिपो, बेगम ब्रिज रोड, मेरठ– 250001, पृ. 324–337।

8. कुमारी, वंदना (2017) भारत में नारी शिक्षा की स्थिति, *IJSRSET,* Volume 3, p. 18-24.

9. https://www.education.gov.in, Assess on 08-02-2024.

10. https://indiaspendhindi.com, Assess on 16-03-2024.

11. जनगणना – 2011।

––==00==––